

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड्जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 63/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अणदाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:11.01.2021

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 87/2013 सरकार बनाम अणदाराम में निर्णय दिनांक 04.09.2013 के तहत मौजा खेरवाड के खसरा नं. 179 रकबा 14 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.12.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.01.2018 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अपीलांट के नायब तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 87/13 के फर्द अहकाम दिनांक 14.8.13 से 04.09.13 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 4.12.16 को पटवारी भागाराम के पास आया तथा उसे कहा कि ट्यूबवेल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है तब अपीलांट ने कहा कि ट्यूबवेल लीज पर है। कोई अतिक्रमण नहीं है। तब पटवारी ने कहा कि आपके विरुद्ध पूर्व में धारा 91 की कार्यवाही चली थी। तब अपीलांट ने कहा कि वह प्रकरण तो निस्तारित हो चुका है। तब पटवारी ने कहा कि आपको उक्त प्रकरण में दोषी पाया है तथा अब उसमें आगे कार्यवाही करनी है। जिस पर अपीलांट को भी शक हुआ, तब अपीलांट न्यायालय में गया तथा आदेश की नकले प्राप्त करने पर उसे आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। इस प्रकार अपीलांट व्यथित पक्षकार है और प्रथम बार जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मयाद है। जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरुद्ध आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)-पटवारी ने जो रिपोर्ट दिनांक 26.7.13 को तैयार करना बताया है। उसमें जो नजरी नक्शा बनाया है। उसमें किसी प्रकार का कोई नाप चोप अंकित नहीं किया है। इसलिये उसके द्वारा जो 14 बीघा भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। वह गलत बताया गया है। खसरा नं. 179 पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट की खातेदारी का खेत गोचर की भूमि के चिपता ही है तथा उसने अपनी खातेदारी की भूमि में पक्की ढाणी बना रखी है। जहां पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। पटवारी ने गलत आधार पर अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की है। जबकि अपीलांट का गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण

नहीं है। पटवारी ने बिना नाप चोप किये ही गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी, जो पूर्णतया गलत है। जिस पर नायब तहसीलदार ने उक्त कार्यवाही को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। जिसके कारण अपीलान्ट कभी भी पुनः अधीनस्थ न्यायालय नहीं गया। किन्तु अपीलान्ट की पीठ पीछे उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसको धोखे में रखकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)—अपीलान्ट का गै.मु. गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। बल्कि उसकी ढाणी खातेदारी की भूमि में है। जहां पर विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। जिसका नाप चोप करने से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। किन्तु पटवारी ने उक्त जायगा का नाप चोप नहीं किया तथा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(IV)—अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो गलत है।


{2}(V)—पटवारी के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र / गवाही भी नहीं ली गई तथा न ही अपीलान्ट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त आदेश जैर अपील अवैध है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा खेरवाड में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खेरवाड के खसरा नंबर 179 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मनोज कुमार )  
अपर अधिवक्ता, नागौर  
नागौर